EDITOR'S SCATVIEW

Manoj Kumar Madhavan

Jio emerged the top bidder for the 5G spectrum auction as it acquired 24,740 MHz spectrum worth Rs 88,078 crore, Airtel came in as the second-highest bidder with 19,867 MHz spectrum worth Rs 43,084 crore. Vodafone Idea snapped up 2,668 MHz worth Rs 18,784 crore. Adani got 400 MHz spectrum in 26 GHz band worth Rs 212 crore.Total bids worth Rs 1,50,173 crore for 71 per cent of total 5G spectrum bid out in this latest auction.

The Zee – Sony merger has got an approval from the Bombay Stock Exchange and National Stock Exchange. This should pave the way for the merger process to be completed in the next six months. Definitely the industry will await this development.

Three consultations papers will pave the way for the next wave of reforms in the broadcast, cable and telecom sectors. The Telecom Regulatory Authority of India has issued the consultation paper on "Renewal of Multi-System Operators (MSOs) Registration".

Digitalization of the Indian broadcasting sector began in year 2012 and was completed across the country by March 2017. Ministry of Information & Broadcasting (MIB) issued first of new registrations to Multi System Operators (MSOs) during the DAS implementation in June 2012, which became due for renewal/ extension in June 2022.The Cable Television Networks Rules, 1994, however, do not mention provision about renewal of MSO registrations. In view of this, the Authority has received a reference from MIB seeking recommendations on the issues pertaining to MSO renewal procedure.

Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) released guidelines for the testing and certification of the conditional access system (CAS) and the subscriber management system (SMS) for the broadcasting sector. The release of the CAS and SMS testing procedures will bring "more transparency" in the entire value chain of the broadcasting sector.

DoT under the Ministry of Communications has sought views on the need for overhauling legal framework governing the telecom sector. The ministry has released a consultation paper regarding this, which suggested the need for a new legal framework which was clear, exact, and in tune with the altering occasions and applied sciences.

TRAI had earlier issued Consultation paper on Issues related to New Regulatory Framework for Broadcasting and Cable services. The authority is issuing this consultation paper for seeking stakeholders' comments on points or issues that are pending for full implementation of New Regulatory Framework 2020.

All of this should usher in a transparency and level playing field for all stakeholders in the industry.

(Manoj Kumar Madhavan)

जियो 5जी स्पेक्ट्रम नीलामी के लिए शीर्ष बोलीदाता के रूप उभरा है, क्योंकि उसने 88,078 करोड़ रुपये के 24,740 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम का अधिग्रहण किया है, एयरटेल 43,084 करोड़ रुपये के 19,867 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम के साथ दूसरी सबसे बड़ी बोलीदाता के रूप में उभरा है। वोडाफोन आइडिया ने 18,784 करोड़ रुपये में 2,668 मेगाहर्ट्ज का अधिग्रहण किया। अदानी को 212 करोड़ रुपये के 26 गीगाहर्ट्ज बैंड में 400 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम मिला। इस नवीनतम नीलामी में कुल 5जी स्पेक्ट्रम की 71 प्रतिशत बोली के लिए 1,50,173 करोड़ रुपये की कुल बोली लगायी गयी।

जी–सोनी विल को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से मंजूरी मिल गयी है। इससे अगले छह महीनों में विलय की प्रक्रिया पूरी होने का मार्ग प्रशस्त होगा। निश्चित रूप से उद्योग इस विकास का इंतजार करेगा।

तीन परामर्श पत्र प्रसारण, केबल और दूरसंचार क्षेत्रों मे सुधारों की अगली लहर का मार्ग प्रशस्त करेंगे। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने 'मल्टी सिस्टम ऑपरेटरों (एमएसओ) के पंजीकरण' पर नया परामर्श पत्र जारी किया है।

भारतीय प्रसारण क्षेत्र का डिजिटलीकरण वर्ष 2012 में शुरू हुआ और मार्च 2017 तक पूरे देश में पूरा हो गया। सूचना और प्रसारण मंत्रालय (एमआई बी) ने जून 2012 में डीएएस कार्यान्वयन के दौरान मल्टी सिस्टम ऑपरेटरों (एमएसओ) को पहला नया पंजीकरण जारी किया, जो जून 2022 में नवीकरण/विस्तार के लिए देय हो जाता है।

हालांकि, केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 में एमएसओ पंजीकरण के नवीकरण के प्रावधान का उल्लेख नहीं है। इसे देखते हुए, प्राधिकरण को एमआईबी से एक संदर्भ पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें एमएसओ नवीकरण प्रक्रिया से संबंधित मुद्दों पर सिफारिशें मांगी गयी हैं।

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने प्रसारण क्षेत्र के लिए कंडीशनल एक्सेस सिस्टम (सीएएस) और ग्राहक प्रबंधन प्रणाली (एसएमएस) के परीक्षण और प्रमाणन के लिए दिशा–निर्देश जारी किये। सीएएस और एसएमएस परीक्षण प्रक्रियाओं को जारी करने से प्रसारण क्षेत्र की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला में 'अधिक पारदर्शिता' आयेगी।

संचार मंत्रालय के तहत दूरसंचार विभाग ने दूरसंचार क्षेत्र को नियंत्रित करने वाले कानूनी ढ़ांचे में बदलाव की आवश्यकता पर विचार मांगा है। मंत्रालय ने इस संबंध में एक परामर्श पत्र जारी किया है, जिसमें एक नये कानूनी ढ़ांचे की आवश्यकता का सुझाव दिया गया है जो स्पष्ट, सटीक और बदलते अवसरों और अनुप्रयुक्त विज्ञान के अनुरूप हो।

ट्राई ने इससे पहले प्रसारण और केबल सेवाओं के लिए नये नियामक ढ़ांचे से संबंधित मुद्दों पर परामर्श पत्र जारी किया था। प्राधिकरण इस परामर्श पत्र को नये नियामक ढ़ांचे 2020 के पूर्ण कार्यान्वयन के लिए लंबित विंदुओं या मुद्दों पर हितधारकों की टिप्पणियों के लिए जारी कर रहा है।

यह सब उद्योग में सभी हित धारकों के लिए एक पारदर्शिता और समान अवसर प्रदान करना चाहिए।

(Manoj Kumar Madhavan)